तीनों महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति देंगे।

15. सेवाओं में आए व्यवधान और उपभोक्ताओं को हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रमिक इस बात पर सहमत हुए कि वे आज 23 जून 1995 को 13.00 बजे तक काम को पूर्णतया सामान्य स्थिति में लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे।

ह०/-
(आर०के० टक्कर)
अध्यक्ष
दूरसंचार आयोग एवम्
सचिव दूरसंचार विभाग
भारत सरकार

ह०/-
(चौ० रघुवीर सिंह)
नेता, कर्मचारी पक्ष
जे०सी०एम०

ह०/-
(ओ०पी० गुप्ता)
महासचिव, एन०एफ०टी०ई०

ह०/-
(आर० वेंकटरमन)
महासचिव, एन०एफ०टी०ओ०

मैं हड़ताल वापस लेने में सहमत हूं।
ह०/- 23.6.95
(सुरेश कुमार)
महासचिव, बी०टी०ई०एफ०

संचार विभाग
संचार भवन
पृष्ठांकन सं० 32-2/95-एसआरटी
दिनांक 23.6.95

प्रति सभी मुख्य महाप्रबंधकों को सूचनार्थ प्रेषित।

सड़कों के निर्माण हेतु विश्व बैंक की मंजूरी

325. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के विभिन्न भागों में सड़क निर्माण हेतु कुछ योजनाओं को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनाएं कौन-कौन सी हैं और उन पर कितनी राशि खर्च की जाएगी और उनके कब तक पूरी होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लगभग 320 कि०मी० लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के सुधार के लिए तथा उड़ीसा में राज्यीय सड़कों पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 306 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण समझौते पर दि० 18.6.92 को विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। इन परियोजनाओं के सन् 2000 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में राज्यीय राजमार्गों के कुछ चुनिंदा खंडों को सुदृढ़ बनाने और चौड़ा करने तथा भागलपुर में गंगा पुल एवं पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध है। इन परियोजनाओं के जून, 1998 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है।

Amount to be gained by DOT from Private Operators

326. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had claimed that the DOT will get an amount of Rs. 1 lakh crore to Rs: 1.25 lakh crores from private operators in cellular and basic telecom services for a period of 15 years; and

(b) if so, what is the break up for such a projection?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) Licences for franchise of Cellular Mobile Telephone Service in 4 metro cities have been granted to 8 Indian companies, two for each city. These licences have been granted for a period of 10 years. The minimum licence fee payable by the licencies over a period of ten years is Rs. 855 crores. However, from 4th year onwards, the licence fee will be linked with number of subscribers @ Rs. 5 lakhs per 100 subscribers and the actual licence fee may be more than the minimum licence fee.

The Govt. has not estimated the amount to be gained from private